



दैनिक समाचार पत्र

भारतार्थ खबर

खबर नहीं, उसका अर्थ

देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया



UNSC में भारत की स्थायी सीट को V4 का समर्थन, जयशंकर ने बताया 'ऐतिहासिक'



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
न्यूयॉर्क, 22 सितंबर 2026। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को यूरोप के चार देशोंपोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्यका समर्थन मिला है। यह समर्थन 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान न्यूयॉर्क में हुई पहली V4 Indi विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक में सामने आया। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लाभार ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के प्रमुख देश और हिंद-प्रशांत

क्षेत्र में उभरती शक्ति के रूप में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान मिलना चाहिए। V4 देशों ने जताया भारत के समर्थन पर साझा रुख विसेग्राद समूह यानी V4 में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य शामिल हैं। बैठक के बाद स्लोवाक विदेश मंत्री जुराज ब्लाभार ने कहा कि चारों देश इस बात पर सहमत हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। उनके अनुसार भारत वैश्विक दक्षिण का महत्वपूर्ण देश है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत लंबे

समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता की मांग करता रहा है। नई दिल्ली का तर्क है कि वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को संयुक्त राष्ट्र की निर्णय लेने वाली संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जयशंकर ने बैठक को बताया नया ऐतिहासिक अवसर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पहली ट4 प्दकप बैठक को एक नया और ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, संपर्क व्यवस्था और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। जयशंकर के अनुसार भारत और V4 देशों के बीच विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित करने तथा वार्षिक बिजनेस फोरम शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी और लोगों की आवाजाही जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया। बैठक में यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के

घटनाक्रम सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। UNSC में सुधार की भारत की मांग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य हैं। इनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका पांच स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव दो वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार परिषद के गैर-प्रक्रियात्मक निर्णयों के लिए नौ सदस्यों के समर्थन की मांग करता रहा है। हालांकि, चार V4 देशों का समर्थन भारत की दावेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक समर्थन है, लेकिन इससे अपने आप परिषद की संरचना में बदलाव नहीं होता। इसके लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन की आवश्यकता होगी। V4 India से आर्थिक और रणनीतिक सहयोग

भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया, एशियन गेम्स में टेबल टेनिस टीमों का शानदार प्रदर्शन

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026। नई दिल्ली। एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल



टेनिस मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत दर्ज की। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने सीधे गेमों में मुकाबले अपने नाम किए और अगले दौर में अपनी जगह मजबूत की। पुरुष टीम स्पर्धा में भारत की ओर से हरमीत देसाई, साथियान ज्ञानशेखरन और पायस जैन ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को

लगातार तीन मुकाबलों में हराया। हरमीत देसाई ने खान मोहम्मद को 11-4, 11-3, 11-5 से शिकस्त दी। इसके बाद कप्तान साथियान ज्ञानशेखरन ने अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9 से हराकर भारत की बढ़त 2-0 कर दी। तीसरे मुकाबले में पायस जैन ने मोहम्मद को 11-2, 11-5, 11-7 से हराकर भारत की जीत पूरी कर दी। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप एफ में अपनी स्थिति मजबूत की और अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम को ईरान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जीत टीम के लिए महत्वपूर्ण रही। महिला टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। सुतीर्था मुखर्जी ने अलीना खान को 11-3, 11-3, 11-4 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद युवा खिलाड़ी सिंद्रेला दास ने कलसूम खान को 11-6, 11-7, 11-5 से हराया। तीसरे

मुकाबले में श्रीजा अकुला ने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से पराजित कर भारतीय महिला टीम को 3-0 से जीत दिलाई। इस जीत के साथ महिला टीम ने ग्रुप एफ में लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत-पाकिस्तान मुकाबलों के दौरान खेल भावना का दृश्य भी देखने को मिला। मुकाबले समाप्त होने के बाद दोनों देशों के खिलाड़ियों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाकर खेल भावना और आपसी सम्मान का संदेश दिया। एशियन गेम्स के तीसरे दिन टेबल टेनिस के अलावा निशानेबाजी और मिश्रित मार्शल आर्ट्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए। ऐसे में भारतीय दल के लिए यह दिन पदक और महत्वपूर्ण जीत के लिहाज से खास रहा। भारत की दोनों टेबल टेनिस टीमों की जीत ने एशियन गेम्स में भारतीय अभियान को मजबूती दी है। अब अगले दौर में खिलाड़ियों के सामने प्रतिযোগिता को आगे बढ़ाने और पदक की दिशा में कदम बढ़ाने की चुनौती होगी।

UPI चार्ज पर वित्त मंत्री की सफाई, होर्मुज संकट के बीच सोहर बना भारत-खाड़ी व्यापार का नया गेटवे

भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर जारी चर्चाओं के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि इसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ आम



ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राहक पहले की तरह यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकेंगे और MDR को उनसे अलग से वसूलने की व्यवस्था नहीं है। वित्त मंत्री ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि MDR को टैक्स या सेस समझना सही नहीं है। यह भुगतान व्यवस्था से जुड़े सेवा प्रदाताओं के बीच लागू होने वाला शुल्क है। सरकार

के अनुसार, इससे प्राप्त राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा नहीं होगी, बल्कि भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े पक्षों के बीच वितरित होगी। 2,000 रुपये तक के भुगतान पर MDR नहीं नए ढांचे के अनुसार, 2,000 रुपये तक के पात्र मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। वहीं 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट चम्तेप्रद-जब-डमटबीदज (P2M) लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा। यह व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR का दायित्व भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के संबंधित पक्षों पर रहेगा और ग्राहक से यूपीआई भुगतान के समय अलग से यह शुल्क लेने की अनुमति नहीं होगी। Person-to-Person यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI लेन-देन पर भी कोई MDR लागू नहीं होगा। करीब 96 प्रतिशत P2M लेन-देन रहेंगे अप्रभावित वित्त मंत्रालय के अनुसार, नए ढांचे के बावजूद लगभग 96

प्रतिशत मर्चेंट UPI लेन-देन अप्रभावित रहेंगे। छोटे व्यापारियों से जुड़े कुछ लेन-देन भी मौजूदा शून्य-MDR व्यवस्था के दायरे में रहेंगे। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य UPI भुगतान प्रणाली के संचालन और दीर्घकालिक विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक ढांचा तैयार करना है। राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत (NPCI) ने 15 सितंबर को नए डक ढांचे की घोषणा की थी। इसके तहत शुल्क का वितरण भुगतान प्रणाली में शामिल बैंकों भुगतान सेवा प्रदाताओं और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच किया जाना है। MDRकोलेकर क्या है विवाद? MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान रवीकार करने वाले व्यापारी के लेन-देन से जुड़ेभुगतान तंत्र मेंलगाया जाता है। नए नियम में 2,000 रुपये से अधिक के कुछ शुल्क को ग्राहक पर डालने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि MDR सरकारी कर या उपकर नहीं है और इससे प्राप्त राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं होगी।



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रभावित समुद्री आवाजाही के बीच ओमान का सोहर बंदरगाह भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक लॉजिस्टिक मार्ग के रूप में उभर रहा है। भारत से सोहर के बीच फीडर जहाज सेवाओं में संकट शुरू होने के बाद करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय मूल के माल को सीधे खाड़ी बंदरगाहों तक भेजने के बजाय कुछ कार्गो अब ओमान पहुंचाकर वहां से सड़क मार्ग के जरिए GCC देशों तक भेजा जा रहा है। सोहर क्यों बन रहा है अहम? सोहर की रणनीतिक अहमियत का एक कारण इसका

भौगोलिक स्थान है। यह ओमान के उत्तरी तट पर स्थित है और होर्मुज जलडमरूमध्य के प्रमुख संकरे समुद्री मार्ग के बाहर है। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव के दौरान यह भारत-खाड़ी व्यापार के लिए अतिरिक्त समुद्री और लॉजिस्टिक में विकल्प उपलब्ध करा सकता है। हालांकि, इसे होर्मुज का पूर्ण विकल्प कहना सही नहीं होगा। खाड़ी क्षेत्र के बड़े बाजारों और आपूर्ति शृंखलाओं की फीडर जहाज सेवाओं में संकट शुरू होने के बाद करीब चार गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इससे संकेत मिलता है कि भारतीय मूल के माल को सीधे खाड़ी बंदरगाहों तक भेजने के बजाय कुछ कार्गो अब ओमान पहुंचाकर वहां से सड़क मार्ग के जरिए GCC देशों तक भेजा जा रहा है। सोहर क्यों बन रहा है अहम? सोहर की रणनीतिक अहमियत का एक कारण इसका

केवल माल ढुलाई केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक निवेश केंद्र के रूप में भी भारतीय कंपनियों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ टर्मिनल संचालन और अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की जा रही है। सोहर फ्रीजोन में भारतीय कंपनियों की तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सोहर पोर्ट का कार्गो कारोबार भी बढ़ा सोहर पोर्ट और फ्रीजोन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में बंदरगाह ने 52 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभाला, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 52 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कंटेनर कारोबार 40 प्रतिशत बढ़कर 5.45 लाख TEU पहुंच गया। पोर्ट पर शिप-टू-शिप कार्गो हैंडलिंग 24.38 मिलियन मीट्रिक टन रही। आधिकारिक आंकड़े सोहर की बढ़ती ट्रांसशिपमेंट और लॉजिस्टिक भूमिका को भी रेखांकित करते हैं। बंदरगाह और फ्रीजोन के पूरे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में 30 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया है। पोर्ट प्रबन्धन के अनुसार, इसकी फ्रीजोन के सीईओ रेंड अल रुबई के अनुसार, पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद भारत और सोहर के

सोहर के पास शिप-टू-शिप ट्रांसफर के जरिए कच्चे तेल की आवाजाही बढ़ाई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब ने अपनी पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन में व्यवधान के बाद सोहर के पास समुद्री जहाजों के बीच कच्चे तेल के हस्तांतरण का इस्तेमाल बढ़ाया है। यह घटनाक्रम बताता है कि ओमान के तट पर मौजूद समुद्री बुनियादी ढांचा मौजूदा संकट में ऊर्जा आपूर्ति शृंखला के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। भारत-ओमान व्यापारिक रिश्तों को मिल सकता है नया आधार। भारत और ओमान के आर्थिक संबंध पहले से मजबूत हैं। भारतीय दूतावास के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.187 अरब डॉलर रहा। वहीं भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। ऐसे में सोहर का बढ़ता महत्व मौजूदा पश्चिम एशिया संकट तक सीमित नहीं माना जा सकता। बंदरगाह भारत को खाड़ी क्षेत्र में व्यापार के लिए एक अतिरिक्त लॉजिस्टिक विकल्प देता है। हालांकि, इसकी वास्तविक दीर्घकालिक उपयोगिता समुद्री सुरक्षा, परिवहन लागत, बीमा, बंदरगाह क्षमता और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कारकों पर निर्भर करेगी।

भारत ने जीता एशियन गेम्स का पहला स्वर्ण

भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह
भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
नई दिल्ली। 22 सितंबर 2026 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के महिला टी-20 फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 45 गेंदों पर 79 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर 48 रन बनाए, जबकि रिचा घोष ने 22 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 69 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लिए, जबकि शेफाली वर्मा, श्रेयांका पाटिल और श्री चरण्णी ने भी गेंदबाजी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की इस जीत के साथ एशियन गेम्स 2026 में देश के खाते में पहला स्वर्ण पदक आया। महिला क्रिकेट टीम के प्रदर्शन ने भारतीय खेल अभियान को नई मजबूती दी है।



भारत-V4 की पहली हाई-लेवल बैठक, सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति



भारतार्थ खबर
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली, 22 सितंबर 2026 भारत और यूरोप के वाइसेग्राद समूह यानी V4 देशों के बीच न्यूयॉर्क में पहली हाई-लेवल बैठक आयोजित हुई। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान हुई, जिसमें भारत और V4 देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में रक्षा, अंतरिक्ष और तकनीक सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे सामने आए। भारत और V4 देशों के बीच हर वर्ष बिजनेस फोरम तथा विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करने पर भी सहमति बनी। बैठक के दौरान V4 देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन की बात भी सामने आई।

T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ की बड़ी रक्षा डील



भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह
Bhaarataarth.com
नई दिल्ली 22 सितंबर 2026 भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। रक्षा मंत्रालय ने

T-72 और T-90 टैंकों के लिए Auxiliary Power Units की खरीद को लेकर 586 करोड़ का करार किया है। यह समझौता नई दिल्ली में किया गया। AuÜiliary Power Unit का इस्तेमाल टैंक की विभिन्न प्रणालियों को

मुख्य इंजन पर निर्भरता कम करते हुए ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी क्षमता और सैन्य उपकरणों के आधुनिकीकरण के बीच इस करार को महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सम्पादकीय

बारिश का पानी संकट क्यों बनता है? शहरों की

तैयारी अब मौसम से आगे सोचनी होगी

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

बारिश प्रकृति का वरदान है, लेकिन जब यही बारिश शहरों की सड़कों पर जलभराव, यातायात जाम और जनजीवन में अव्यवस्था का कारण बनने लगे तो सवाल केवल मौसम का नहीं रह जाता। सवाल शहर की तैयारी, उसके जलनिकासी तंत्र, सड़क निर्माण, झीलों और नालों की स्थिति तथा प्रशासनिक समन्वय का भी है। कर्नाटक में इस समय मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 23 सितंबर को राज्यभर में ऑरेंज अलर्ट और 24 सितंबर को तटीय क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यह स्थिति ऐसे समय में है जब सितंबर में राज्य में बारिश सामान्य से काफी कम रही है। यानी एक तरफ बारिश की कमी और दूसरी तरफ कुछ घंटों की तेज बारिश से जलभराव यह विरोधाभास आज के शहरों की जल-व्यवस्था के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। बारिश समस्या नहीं, कमजोर व्यवस्था समस्या है बेंगलुरु में सोमवार को हुई बारिश के बाद कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ। बी. नारायणपुरा मेन रोड, मराठाहल्ली, कडुब्रीसनहल्ली, वरथुर कोडी, कृष्णराजपुरम आउटर रिंग रोड और अन्य इलाकों में यातायात पर असर पड़ा। कुछ स्थानों पर जलनिकासी के लिए नालियों के जाम इनलेट साफ करने पड़े। यह तस्वीर केवल बेंगलुरु की नहीं है। देश के अनेक तेजी से बढ़ते शहरों में बारिश के दौरान यही समस्या अलग-अलग रूपों में सामने आती है। शहरों का विस्तार हुआ, सड़कें बढ़ीं, कंक्रीट का क्षेत्र बढ़ा, लेकिन प्राकृतिक जलप्रवाह के रास्तों और वर्षाजल संचयन की क्षमता उसी गति से नहीं बढ़ी। इसलिए अब यह सोच बदलने की जरूरत है कि हर भारी बारिश के बाद कुछ घंटों के लिए पानी निकाल देना ही समाधान है। जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान बारिश शुरू होने के बाद नहीं, बारिश आने से पहले तैयार होना चाहिए। नालियां केवल सफाई का विषय नहीं बारिश के पानी की निकासी के लिए नालियां और राजकालुवे शहर की जीववरंछा हैं। लेकिन कई स्थानों पर उनमें गद, कचरा और अतिक्रमण जलप्रवाह को बाधित करते हैं। ऐसे में तेज बारिश का पानी सड़क पर अघाते लगाता है। बेंगलुरु में हालिया बारिश के बाद पूर्वी क्षेत्र के अधिकारियों को निचले इलाकों में जलभराव रोकने, नालियों की सफाई, पंपिंग व्यवस्था को सक्रिय रखने और बंद मैनहोल तथा जलनिकासी तंत्र को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यह तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन दीर्घकालिक नीति का सवाल इससे बड़ा है। हर वर्ष बारिश से पहले वही नालियां क्यों साफ करनी पड़ती हैं? जलप्रवाह में रुकावट पैदा करने वाले कारणों का स्थायी पहचान और समाधान क्यों नहीं होता? क्या शहर के प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र का वर्षाजल प्रबंधन मानचित्र तैयार नहीं किया जा सकता? झीलों को केवल सौंदर्य स्थल न समझें बेंगलुरु जैसे शहरों में झीलें केवल पर्यटन या मनोरंजन के केंद्र नहीं हैं। वे वर्षाजल को रोकने, भूजल पुनर्भरण और प्राकृतिक जलप्रवाह को बनाए रखने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्रकाशित अध्ययन में बेंगलुरु के शहरी बाढ़ संकट के संदर्भ में झीलों और जल निकायों के बीच प्राकृतिक संपर्क टूटने, जलधारण क्षमता में कमी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। अध्ययन ने यह भी कहा कि भारी वर्षा की घटनाओं के लिए शहरों की तैयारी मजबूत करना आवश्यक है। इसलिए झीलों का संरक्षण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं, बल्कि शहरी बाढ़ प्रबंधन और जल सुरक्षा की संयुक्त नीति होना चाहिए। सड़क निर्माण में वर्षाजल की जगह कहाँ है? शहरों में सड़कें विकास का प्रतीक हैं, लेकिन सड़क निर्माण के साथ यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि बारिश का पानी जाएगा कहाँ? यदि हर खाली जमीन, हर खुला क्षेत्र और हर प्राकृतिक जलप्रवाह प्रबंधन में बदल जाएगा तो वर्षाजल के जमीन में उतरने की संभावना घटेगी। पानी तेजी से सतह पर बहेगा और कम समय में नालियों पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए नई सड़क, फ्लाईओवर, भवन या कॉलोनी की योजना बनाते समय केवल यातायात और निर्माण लागत नहीं, बल्कि वर्षाजल प्रबंधन की पूरी श्रृंखला को अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत कार्य नहीं बारिश से जुड़ी आपदा में प्रशासन का काम केवल पानी निकालना, यातायात नियंत्रित करना या प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना नहीं होना चाहिए। असली आपदा प्रबंधन वह है जो संकट आने से पहले संभावित जोखिमों की पहचान कर ले। हर शहर में ऐसे क्षेत्रों की सूची होनी चाहिए जहां भारी बारिश में जलभराव की संभावना अधिक है। इन क्षेत्रों में पंप, बिजली बैकअप, वैकल्पिक यातायात मार्ग, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और संचार व्यवस्था पहले से तैयार होनी चाहिए।

बाड़ाबंदी की राजनीति और लोकतंत्र पर बढ़ता अविश्वास



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था का नाम नहीं है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है जनता का विश्वास, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही, राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और जनादेश का सम्मान। जब चुनाव समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दलों को अपने ही निर्वाचित या संभावित निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक साथ रखने के लिए रिसॉर्ट, होटल या अन्य सुरक्षित स्थानों का सहारा लेना पड़े, तब यह दृश्य केवल राजनीतिक रणनीति का विषय नहीं करता है। राजस्थान के हालिया नगर निकाय चुनावों के बाद ऐसी बाड़ाबंदी की खबरें सामने आई हैं। चुनाव परिणामों से पहले भी कई स्थानों पर प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कवायद की रिपोर्टें आईं और परिणामों के बाद उन निकायों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मीडिया रिपोर्टें के

अनुसार, कई जगह निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई और अध्यक्ष या सभापति के चुनाव को लेकर दलों ने अपने-अपने सदस्यों को साथ रखने की कोशिश की। यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर राजनीतिक दलों को मतदान के बाद भी पूरा भरोसा नहीं रहता? बाड़ाबंदी आखिर किसका संकेत है? बाड़ाबंदी को राजनीतिक दल अक्सर संभावित दल-बदल, क्रॉस वोटिंग या खरीद-फरोख्त से बचाव की रणनीति के रूप में देखते हैं। हालिया राजस्थान निकाय चुनावों के संदर्भ में भी मीडिया रिपोर्टें में यही आशंकाएं सामने आईं। कुछ दलों ने बाड़ाबंदी जैसे शब्दों के इस्तेमाल या उसके राजनीतिक अर्थ से दूरी भी बनाई है। इसलिए किसी भी दल पर खरीद-फरोख्त का आरोप केवल राजनीतिक चर्चा के आधार पर तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का लोकतांत्रिक पक्ष इससे कहीं बड़ा है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होते। वे जनता के मत से निर्वाचित होते हैं। राजनीतिक दल उन्हें चुनाव का नंग और संगठन देते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधित्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राजस्थान के हालिया नगर निकाय चुनावों के बाद ऐसी बाड़ाबंदी की खबरें सामने आई हैं। चुनाव परिणामों से पहले भी कई स्थानों पर प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कवायद की रिपोर्टें आईं और परिणामों के बाद उन निकायों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुईं जहां किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मीडिया रिपोर्टें के

पीछे धन का लेन-देन हुआ है। ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस प्रमाण आवश्यक हैं। फिर भी, यदि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का राजनीतिक रुख व्यक्तिगत लाभ, पद या आर्थिक प्रलोभन से प्रभावित होता है, तो यह मतदाता के विश्वास और लोकतांत्रिक बन सकता है। भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची दल-बदल के कुछ मामलों में अयोग्यता का प्रावधान करती है। निर्वाचन आयोग भी दल-बदल संबंधी वैधानिक व्यवस्था और चुनाव कानूनों को अपने आधिकारिक संसाधनों में दर्ज करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न मामलों में दल-बदल और राजनीतिक निष्ठा बदलने से उत्पन्न लोकतांत्रिक समस्याओं पर ख़िला व्यक्त की है। एक फैसले में न्यायालय ने कहा कि दल-बदल से जुड़े प्रलोभन और पद की चाह से जुड़ी भ्रष्ट या अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर विचार होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर राजनीतिक बदलाव लोकतंत्र-विरोधी है। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद, विचार परिवर्तन और राजनीतिक पुनर्संरूपन भी होते हैं। लेकिन मतदाता के विश्वास और सार्वजनिक दायित्व को व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ से ऊपर रखना लोकतांत्रिक नैतिकता का मूल प्रश्न है। चुनाव केवल मतदान का दिन नहीं हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी कमजोरी यह है कि जनता की राजनीतिक सक्रियता अक्सर मतदान के दिन तक सीमित हो जाती है। चुनाव के समय प्रत्याशी घर-घर पहुंचता है, मतदाताओं से समर्थन मांगता है, घोषणाएं करता है और विकास के वादे करता है। चुनाव जीतने के बाद वही जनता अक्सर

अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने में संकोच करती है। यहीं लोकतंत्र का संतुलन कमजोर पड़ता है। लोकतंत्र का अर्थ केवल यह नहीं कि पांच वर्ष में एक बार वोट डाल दिया और जिम्मेदारी समाप्त हो गई। मतदान जनता के अधिकार की शुरुआत है; उसके बाद निर्वाचित प्रतिनिधि के कामकाज पर नजर रखना भी नागरिक जिम्मेदारी का हिस्सा है। सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्थानीय विकास और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर जनता को अपने प्रतिनिधियों से नियमित सवाल पूछने चाहिए। चुनावी घोषणाओं और वास्तविक काम के बीच कितना अंतर रहा, इसका सार्वजनिक मूल्यांकन होना चाहिए। जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण राजनीतिक जवाबदेही केवल राजनीतिक दलों से नहीं आती। उसके लिए जागरूक नागरिक समाज आवश्यक है। यदि मतदाता जाति, धर्म, क्षेत्र, व्यक्तिगत संबंध या तत्काल राजनीतिक लाभ के आधार पर अपने प्रतिनिधियों के काम का मूल्यांकन करना छोड़ देता है, तो जवाबदेही कमजोर होती है। इसके विपरीत यदि नागरिक अपने प्रतिनिधि से तथ्य और काम के आधार पर सवाल पूछता है, तो राजनीति का केंद्र धीरे-धीरे व्यक्ति और दल से हटकर सार्वजनिक हित की ओर जाता है। जनता को यह अधिकार है कि वह शक्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछे। लेकिन सवाल पूछने के साथ प्रमाणित सूचना, संयम और तथ्यपरकता भी जरूरी है। लोकतांत्रिक विरोध का अर्थ व्यक्तिगत अपमान या राजनीतिक वैमनस्य नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही की मांग है। बाड़ाबंदी से बड़ा सवाल

राजनीतिक संस्कृति का बाड़ाबंदी की तस्वीरें देखकर केवल राजनीतिक दलों को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन समस्या इससे कहीं गहरी है। जब तक राजनीतिक व्यवस्था में यह धारणा बनी रहेगी कि चुनाव जीतने के बाद सत्ता का गणित कुछ व्यक्तियों की निष्ठा बदलने से बदल सकता है, तब तक बाड़ाबंदी जैसी रणनीतियां अलग-अलग रूपों में दिखाई देती रहेंगी। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विश्वास का संबंध विकसित करें। उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता बढ़े, स्थानीय प्रतिनिधियों की राजनीतिक और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विश्वास का संबंध विकसित करें। उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता बढ़े, स्थानीय प्रतिनिधियों की हालिया घटनाएं प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए जहां कानून का उल्लंघन या निषिद्धि प्रतिनिधियों की खरीद-फरोख्त के ठोस प्रमाण सामने आएँ। सम्पादकीय दृष्टि राजस्थान की हालिया घटनाएं भारतीय लोकतंत्र के सामने कोई एक दल-विशेष की समस्या नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक संस्कृति पर विचार करने का अवसर हैं। जनता ने जिस प्रतिनिधि को वोट दिया है, उसके बारे में चुनाव परिणाम आने के बाद यह चर्चा होना कि वह किस खेमे में जाएगा, किसके समर्थन में वोट देगा या उसे किस रिसॉर्ट में रखा जाएगा लोकतंत्र को उस मूल भावना को कमजोर करता है जिसमें मतदाता अपने प्रतिनिधि को सार्वजनिक विश्वास सौंपता है। यह भी ध्यान रखना होगा कि बाड़ाबंदी अपने आप में किसी अवैध कृत्य का प्रमाण नहीं है। राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को संगठित रखने के लिए अनेक रणनीतियां अपनाते हैं। लेकिन यदि

ऐसी रणनीति राजनीतिक खरीद-फरोख्त की आशंका से प्रेरित है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए असली चुनौती उस आशंका को जन्म देने वाली राजनीतिक संस्कृति है। समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं होगा। राजनीतिक दलों को आंतरिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और नैतिक जवाबदेही मजबूत करनी होगी। जनता को भी चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखना होगा। मीडिया को आरोपों और तथ्यों के बीच स्पष्ट अंतर रखते हुए प्रमाण आधारित रिपोर्टिंग करनी होगी। निष्कर्ष रु सत्ता नहीं, विश्वास बचाना जरूरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी सत्ता नहीं, जनता का विश्वास है। चुनाव में जीत किसी प्रतिनिधि को पद दे सकती है, लेकिन उसे लोकतांत्रिक सम्मान जनता का विश्वास ही देता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों को सम्मानने के लिए बाड़ाबंदी जरूरी समझी जाने लगे और जनता को अपने ही चुने प्रतिनिधि के राजनीतिक रुख पर संदेह होने लगे, तो यह पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए आत्मस्थान का समय है। चुनाव के पहले नेता जनता के बीच जाते हैं और चुनाव के बाद जनता को नेताओं के काम का हिसाब मांगना चाहिए। यही लोकतंत्र का स्वाभाविक संतुलन है। मतदान लोकतंत्र का अंत नहीं, जवाबदेही की शुरुआत है। जब नागरिक जागरूक होकर प्रश्न पूछेंगे, प्रतीति अपने वादों और फैसलों के लिए सार्वजनिक रूप से जवाब देंगे और राजनीतिक दल जनादेश को सर्वोच्च मानेंगे, तभी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा। क्योंकि अंततः किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत संस्था नहीं, और किसी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी धन या पद नहीं जनता का विश्वास है।

कार्तिक आर्यन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, चंदू चौंपियन के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सम्मान



भारतार्थ खबर संवाददाता अशोक कुमार सिंह Bhaarataarth.com एकता नगर, गुजरात 22 सितंबर 2026 भारतीय सिनेमा के प्रतिष्ठित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में अभिनेता कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चौंपियन में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मंगलवार को गुजरात के एकता नगर में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित किया। यह कार्तिक आर्यन का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। चंदू चौंपियन में कार्तिक आर्यन ने पेरालीपिक स्वर्ण पदक विजेता नुरलीकांत पेटकर से प्रेरित किरदार निभाया था। फिल्म में एक ऐसे खिलाड़ी की संघर्ष यात्रा को सामने रखा गया

है, जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। कार्तिक ने इस भूमिका के लिए शारीरिक बदलाव और प्रशिक्षण पर भी विशेष मेहनत की थी। राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान कार्तिक आर्यन के लिए यह सम्मान उनके अभिनय सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है। खास बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इस वर्ष ममूदी के साथ साझा किया गया। ममूदी को मलयालम फिल्म ठत्तंउलंनहंड के लिए यह सम्मान मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का यह संस्करण वर्ष 2024 की पात्र फिल्मों और सिनेमाई उपलब्धियों को सम्मानित करता है। पुरस्कारों की घोषणा जुलाई 2026 में की गई थी, जबकि सम्मान

समारोह 22 सितंबर को आयोजित हुआ। पहली बार दिल्ली से बाहर समारोह 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की एक विशेष बात इसका आयोजन स्थल रहा। इस बार समारोह मंच पर मिली पहचान कार्तिक आर्यन के लिए यह सम्मान उनके अभिनय सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हो गया है। खास बात यह है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इस वर्ष ममूदी के साथ साझा किया गया। ममूदी को मलयालम फिल्म ठत्तंउलंनहंड के लिए यह सम्मान मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का यह संस्करण वर्ष 2024 की पात्र फिल्मों और सिनेमाई उपलब्धियों को सम्मानित करता है। पुरस्कारों की घोषणा जुलाई 2026 में की गई थी, जबकि सम्मान

निर्देशक का पुरस्कार मिला। कार्तिक के करियर में नया अध्याय कार्तिक आर्यन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का यह सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं, बल्कि अभिनय के क्षेत्र में उनके अब तक के सफर की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है। चंदू चौंपियन की चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए मिले इस सम्मान ने फिल्म और अभिनेता दोनों को राष्ट्रीय सिनेमा के प्रतिष्ठित मंच पर नई पहचान दी है। भारतीय फिल्म जगत में अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों, कलाकारों और तकनीकी प्रतिभाओं को सम्मान मिला। Article 370' को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और Amaran के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ

आखिर इंसान को चाहिए क्या ?



प्रेषक, लेखक, विचारक मोहनलाल मालवी इसरो वैज्ञानिक बेंगलुरु 94482 28817

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com जीवन की भागदौड़ में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर लगातार मौजूद रहते हैं। मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है, रोजगार तलाशता है, धन कमाता है, घर बनाता है, परिवार की प्रेमदारियां निभाता है और सामाजिक ज़िम्मेदा हासिल करने की कोशिश करता है। हर उपलब्धि के बाद कुछ समय के लिए संतोष मिलता है, लेकिन फिर एक नई इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे में एक दिन मन स्वाभाविक रूप से पूछता हैकू आखिर इंसान को चाहिए क्या? यह प्रश्न केवल व्यक्तिगत जीवन का नहीं,

बल्कि आज के सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण अंग है। विकास, सफलता और समृद्धि आवश्यक हैं, लेकिन यदि इनकी दौड़ में मनुष्य अपनी शांति, रिश्ते और संवेदनशीलता छो दे, तो विकास की दिशा पर विचार करना जरूरी हो जाता है। बचपन से शुरू होती है मंजिलों की दौड़ मनुष्य के जीवन में इच्छाओं का सिलसिला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। बचपन में अच्छी पढ़ाई का लक्ष्य होता है। फिर अच्छी नौकरी, बेहतर पद, अपना घर, आर्थिक सुखआ और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की चिंता सामने आती है। इनमें से कोई भी इच्छा गलत नहीं है। शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सुखआ स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं। समस्या यह पैदा होती है जब उपलब्धि की कोई अंतिम सीमा ही न रहे और मनुष्य अपनी जरूरत तथा लालसा के बीच अंतर करना भूल जाए। एक मंजिल हासिल होे ही दूसरी मंजिल सामने आ जाती है। पैसा साधन से उद्देश्य बन जाता है और सफलता तुलना का माध्यम। दूसरों के पास क्या है, यह प्रश्न धीरे-धीरे इस प्रश्न पर भारी पड़ने लगता है कि हमें वास्तव में कितना चाहिए। यही से जीवन की गति और जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर दिखाई देने लगता है। आर्थिक सफलता

जरूरी, लेकिन पर्याप्त नहीं आज के दौर में आर्थिक मजबूती का महत्व नकारा नहीं जा सकता। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आय आवश्यक है। व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है, तो इसके लिए मेहनत और आर्थिक प्रगति स्वाभाविक है। लेकिन धन की उपयोगिता और धन की लालसा में अंतर है। जब पैसा परिवार की जरूरतें पूरी करने का साधन है, तब वह जीवन को सुरक्षित बनाता है। लेकिन धन ही जीवन की सफलता का एकमात्र पैमाना बन जाए, तब व्यक्ति के सामने लगातार अधिक पाने की बेचौनी खड़ी हो सकती है। धन बढ़ने के साथ यदि संतोष, संबंध और सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ें तो समृद्धि का अर्थ हो सकता हो जाता है। लेकिन यदि संपत्ति बढ़ती जाए और संवेदना घटती जाए, तो व्यक्ति के पास साधन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन संतोष कम हो सकता है। जब व्यक्ति में अवसर दिखाई देने लगे आधुनिक समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। नौकरी, व्यापार, पद, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान के लिए संघर्ष स्वाभाविक है। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा का एक चिंताजनक पक्ष तब सामने आता है जब मनुष्य दूसरे मनुष्य को केवल अवसर के रूप में देखने लगे।

किसी के पास धन है तो उससे लाभ की उम्मीद, किसी के पास पद है तो उससे काम निकालने की कोशिश और किसी के पास प्रभाव है तो उससे संबंध बनाने की आकांक्षा यदि रिश्तों की बुनियाद लगातार स्वार्थ पर टिकने लगे, तो सामाजिक विश्वास कमजोर होता है। यह स्थिति किसी एक वर्ग या पीढ़ी तक सीमित नहीं है। इसलिए इसका समाधान भी केवल दूसरों से शिकायत करने में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार की समीक्षा से शुरू होना चाहिए। क्या हमने 'हम' को पीछे छोड़ दिया? भारतीय सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता सामूहिकता रही है। गांवों और कस्बों में लंबे समय तक पड़ोसी का सुख-दुख पूरे समुदाय का विषय माना जाता रहा। किसी व्यक्ति में विवाद हो तो आसपास के लोग सहयोग करते थे और किसी घर में संकट आए तो लोग साथ खड़े होते थे। समय के साथ जीवनशैली बदली है। शहरीकरण, व्यस्तता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी जीवन ने सामाजिक संबंधों के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। आज संपर्क के साधन पहले से कहीं अधिक हैं, लेकिन व्यक्तिगत संवाद और साथ होने का अनुभव कई लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आज समाज में संवेदना

समाप्त हो गई है। देशभर में लोग आपदा, बीमारी, दुर्घटना और सामाजिक संकट के समय एक-दूसरे की सहायता करते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं और नागरिक समूह भी अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी संवेदना और पड़ोसीपन की संस्कृति को मजबूत करने की आवश्यकता बनी हुई है। विरासत में संपत्ति या संस्कार? जीवन में आदर्श व्यक्तित्वों का महत्व इसलिए है कि वे सफलता की अलग परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और कर्तव्यबोध के संदर्भ वाली पीढ़ियों को हम केवल आर्थिक संपत्ति देना चाहते हैं या मूल्य और चरित्र भी। संपत्ति जीवन को सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन चरित्र जीवन को दिशा देता है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आर्थिक सुखआ और बेहतर अवसर चाहिए हैं, लेकिन उनके साथ ईमानदारी, श्रम, संवेदना और जिम्मेदारी के संस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन की असली कमाई क्या है? मनुष्य जन्म के साथ कोई संपत्ति लेकर नहीं आता और मृत्यु के समय भौतिक संपत्ति साथ नहीं ले जाता। यह जीवन का सर्वमान्य

सत्य है। फिर भी मनुष्य का अधिकांश समय संग्रह में बीत जाता है। प्रश्न यह नहीं कि धन कमाना चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है कि धन कमाते समय हम क्या खो रहे हैं। क्या परिवार के लिए समय बच रहा है? क्या माता-पिता के साथ बैठने का अवसर मिला रहा है? क्या बच्चों से संवाद हो रहा है? क्या मित्रता केवल सामाजिक संपर्क तक सीमित हो रही है? क्या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए हमारे पास समय और संवेदना है? इन प्रश्नों के उत्तर जीवन की वास्तविक गुणवत्ता का संकेत दे सकते हैं। सम्पादकीय दृष्टिकोण आधुनिक जीवन में सफलता को केवल त्याग या गरीबी के रूप में देखना भी उचित नहीं होगा। आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और बेहतर जीवन की आकांक्षा चरित्र भी। संपत्ति जीवन को सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन चरित्र जीवन को दिशा देता है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, आर्थिक सुखआ और बेहतर अवसर चाहिए हैं, लेकिन उनके साथ ईमानदारी, श्रम, संवेदना और जिम्मेदारी के संस्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन की असली कमाई क्या है? मनुष्य जन्म के साथ कोई संपत्ति लेकर नहीं आता और मृत्यु के समय भौतिक संपत्ति साथ नहीं ले जाता। यह जीवन का सर्वमान्य

साथ मानसिक शांति, व्यक्तिगत सफलता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और महत्वाकांक्ष के साथ मानवीय संवेदना। इंसान को हर इच्छा पूरी करने के बजाय यह समझने की आवश्यकता है कि कौन-सी इच्छा वास्तव में जीवन को बेहतर बनाती है और कौन-सी केवल तुलना और प्रदर्शन से पैदा हुई है। समय रहते समझना जरूरी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह हो सकती है कि व्यक्ति भविष्य सुरक्षित करने के प्रयास में वर्तमान खो दे। वह बच्चों के भविष्य के लिए इतना काम करे कि बच्चों के साथ वर्तमान बिताने का समय ही न बचे। वह प्रतिष्ठा बनाने में इतना व्यस्त हो जाए कि अपने वास्तविक रिश्तों से दूर हो जाए। समय लौटकर नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, संपत्ति फिर बनाई जा सकती है और कुछ अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जीवन के किसी पड़ाव पर रुककर यह पूछना जरूरी है कि हम क्या हासिल कर रहे हैं और किस कीमत पर। निष्कर्ष रु सफलता से आगे भी एक जीवन है आखिर इंसान को चाहिए क्या? शायद इसका कोई एक सार्वभौमिक उत्तर नहीं है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और आकांक्षाएं अलग होती हैं। किसी

के लिए आर्थिक सुखआ सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है, तो किसी के लिए परिवार, स्वास्थ्य, सेवा या आत्मिक संतोष। लेकिन इतना निश्चित है कि मनुष्य की जरूरतें केवल भौतिक नहीं हैं। उसे भोजन और घर चाहिए, लेकिन साथ ही अपनापन भी चाहिए। उसे धन चाहिए, लेकिन विश्वास भी चाहिए। उसे सम्मान चाहिए, लेकिन रिश्ते भी चाहिए। उसे सफलता चाहिए, लेकिन उस सफलता का अर्थ भी चाहिए। जीवन की अंतिम उपलब्धि शायद यह नहीं कि हमारे पास कितना था, बल्कि यह है कि हमारे होने से कितनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार को समय दे सका, जरूरतमंद की सहायता कर सका, अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहा, अपने माता-पिता और बुढ़ों का सम्मान कर सका, बच्चों को संस्कार दे सका और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सका, तो उसकी जीवन-यात्रा केवल उपलब्धियों की सूची नहीं रह जाती वह अर्थपूर्ण बन जाती है। इसलिए शायद जीवन का प्रश्न यह नहीं कि "मैंने कितना कमाया?" बल्कि यह भी होना चाहिए कि "मैंने कितना जिया, कितना बांटा और कितनों के काम आया?" धन, पद और संपत्ति जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं।

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु दिल्ली और यार्थ राकेश माने की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों निशानेबाजों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उनके प्रदर्शन में फोकस, निरंतरता और टीमवर्क की सराहना की तथा भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी जतायीं। भारतीय निशानेबाजी दल के लिए एशियन गेम्स में यह उपलब्धि महत्वपूर्ण रही है। इससे पहले रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक भी हासिल किया था। भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी रहने के साथ एशियन गेम्स में देश की पदक उम्मीदें भी चर्चा में बनी हुई हैं।

